आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, शुक्रवार 03 जुलाई 2026

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 212
■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

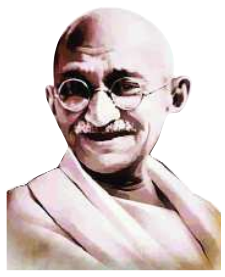

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

खाली प्लॉट बना दिया मेडिकल कचरे का डंपिंग ग्राउंड!

पेज-2

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' देखकर भावुक हुईं कृति

पेज-5

अगस्त अंत में शुरू होगा बायपास एमआर 10 फ्लायओवर

पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 9 करोड़ की हाई-क्वालिटी चरस जब्त, 3 तस्कर अरेस्ट
- बेंगलुरु में बच्चों से अत्याचार का मामला : वीडियो वायरल होने के बाद हुई पहली गिरफ्तारी
- मुंबई : कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना
- अडाणी ग्रुप के फैसले से केरलम सरकार हैरान : बिना परामर्श हिस्सेदारी बेचने पर तकरार
- अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सियासी घमासान : स्कूल में केक काटने पर हेडमास्टर पर गिरी गाज
- मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्कर अरेस्ट : बैंकॉक से लाया 1.23 करोड़ का गोल्ड बार
- सम्राट चौधरी का कड़ा अल्टीमेटम : मंत्री हो या अधिकारी, भ्रष्टाचार पर होगी सख्त कार्रवाई
- गुजरात के वलसाड में बाढ़ जैसे हालात : सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन बेपटरी
- कांगो में इबोला के मामलों में बढ़ोतरी, 1,460 संक्रमित

पीएम मोदी का 'मास्टर स्ट्रोक'

अमित शाह होंगे देश के उपप्रधानमंत्री!

नई दिल्ली (एजेंसी) • केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कौन मंत्री बनेगा, किसका विभाग बदलेगा और किसे संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी—इन सवालों के बीच सत्ता के गलियारों में एक ऐसी चर्चा तेजी से तैर रही है जिसने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। चर्चा यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सरकार में उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस चर्चा की न तो सरकार ने पुष्टि की है और न ही सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई आधिकारिक संकेत मिला है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संभावित 'मास्टर स्ट्रोक' के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले एक दशक में अमित शाह ने सरकार और संगठन दोनों में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। जम्मू-कश्मीर से जुड़े फैसले, आंतरिक सुरक्षा, सहकारिता मंत्रालय और चुनावी रणनीति जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल किया है।

यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच उनका नाम उपप्रधानमंत्री पद के लिए सामने आने लगा है। यदि ऐसा होता है तो इसे केवल पदोन्नति नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की भविष्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा का संकेत भी माना जाएगा।

सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों को देखते हुए सरकार कुछ बड़े प्रतीकात्मक और रणनीतिक फैसले ले सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार केवल नए चेहरों को शामिल करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संदेश देने का माध्यम भी बन सकता है।

राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री सरकार को नया राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश देना चाहते हैं, तो इस बार सबसे बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि इस चर्चा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे लेकर फुसफुसाहट लगातार तेज होती जा रही है।

आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी उपचुनाव की राह

नरोत्तम मिश्रा की राजनीति की दिशा तय करेगा दतिया उपचुनाव, हलचल हुई तेज

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। भाजपा इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने के साथ-साथ संगठनात्मक एकजुटता साबित करने की चुनौती भी होगी।

दिग्गज भाजपा नेता एवं पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। दतिया विधानसभा सीट नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ रही है। हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने उन्हें पराजित कर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था। भाजपा के दिग्गज नेता की इस हार ने पूरे प्रदेश का ध्यान दतिया की ओर खींचा था। अब राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव की नौबत आई है। पिछले कुछ महीनों में नरोत्तम मिश्रा ने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बढ़ाया है और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि भाजपा यह सीट वापस जीतने में सफल रहती है, तो प्रदेश की राजनीति में मिश्रा की भूमिका पहले की तरह प्रभावशाली हो सकती है। वहीं, हार की स्थिति में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।

मोहन सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में तीसरा उपचुनाव-मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में तीसरी बार किसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले हुए दो विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीतकर बराबरी का प्रदर्शन किया था। ऐसे में दतिया उपचुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।

सिंहस्थ 2028 से पहले ही मिलेगा हाई स्पीड का तोहफा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • मध्य प्रदेश स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को खंडवा और इंदौर से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।

इस संबंध में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने गुरुवार को ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे का लक्ष्य सिंहस्थ-2028 से पहले इस परियोजना को पूरा कर श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों को रेल सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि ब्रॉड गेज लाइन, अंडरपास, पुल और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे करने के लिए रेलवे लगातार प्रयासरत है।

फिर खड़े हो रहे अवैध यूनिपोल, निगम अफसरों की मिलीभगत पर उठे सवाल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शहर के प्रतिबंधित और नो-एड जोन में एक बार फिर अवैध यूनिपोल और होर्डिंग खड़े होने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन संरचनाओं को पूर्व में विरोध और कार्रवाई के बाद हटाया गया था, वही खेल अब दोबारा शुरू हो गया है। इससे नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नगर निगम की जनकार्य एवं उद्यान समिति के प्रभारी राजेन्द्र राठौर ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर सयाजी चौराहे से विजय नगर और रेडिसन चौराहे तक मेट्रो कॉरिडोर के सेंट्रल डिवाइडर पर लगाए जा रहे अवैध यूनिपोल, होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री को तत्काल हटाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह क्षेत्र नो-स्टरलाइजेशन/नो-एड जोन घोषित है, जहां किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद विज्ञापन एजेंसियां न केवल यूनिपोल खड़े कर रही हैं, बल्कि उनके लिए फाउंडेशन तक तैयार किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि यह सब बिना अधिकारियों की जानकारी और संरक्षण के कैसे संभव है? राठौर के अनुसार मेट्रो कॉर्पोरेशन ने भी इन अवैध विज्ञापनों पर आपत्ति दर्ज कराई है। मेट्रो से प्राप्त लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि से निगम ने सेंट्रल डिवाइडर और मीडियन विकसित किए थे तथा आकर्षक पौधारोपण कराया था। अब अवैध यूनिपोल लगाने के लिए इन संरचनाओं और हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि निगम अधिकारियों ने नियमों और टेंडर शर्तों को जानते हुए भी विज्ञापन एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए आंखें मूंद रखी हैं।

मुख्यमंत्री की 'A+' नोटशीट दबाने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गंभीर प्रकृति के आवेदनों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री की ओर से विभागों को ए प्लस में नोटशीट भेजी जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीन दिन के भीतर इन मामलों का निराकरण कर सूचित किया जाए लेकिन कई विभागों द्वारा इसमें कार्रवाई न करने की शिकायतें मिली हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में ए प्लस मॉनिट प्रकरणों की समीक्षा बैठक बुलाई है।

लापरवाही करने वाले नपेंगे-इसमें बिना उचित कारण के अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी विभागों को समीक्षा की सूचना दी गई है। साथ ही

अधिकारियों को आवश्यक जानकारी साथ शामिल होने को कहा गया है। इसे लेकर प्रस्तुतीकरण व पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा होगी।

राम मंदिर चंदा कांड में एक और महा-खुलासा

'मुन्नाभाई' टिन्नू यादव ने बना रखा था वीआईपी दर्शन का अवैध वसूली नेटवर्क

अयोध्या (एजेंसी) • अयोध्या अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे गहराई में जा रही है, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार और धोखेबाज़ी की ऐसी परतें खुल रही हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है।

मामले की कमान संभाल रही विशेष जांच दल (एसआईटी) के हाथ अब एक और बेहद सनसनीखेज सुराग लगा है। जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रभु श्रीराम के दर्शन के नाम पर एक 'संगठित वसूली रैकेट' बना रखा था। यह शातिर गिरोह देश-विदेश से आने वाले भोले-भले श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर

हर दिन लाखों रुपये ऐंठता था और शाम होते ही इस काली कमाई का आपस में बंदरबांट कर लिया जाता था। जनवरी में हुई भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब अयोध्या में रामभक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हुआ, तो इस गिरोह ने आपदा में अवसर तलाश लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लंबी लाइनों का फायदा उठाकर वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का यह गंदा खेल बेहद बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। एसआईटी की प्रारंभिक जांच इस बात की ओर पुख्ता संकेत कर रही है कि इस रैकेट में सिर्फ गिरफ्तार हो चुके 8 आरोपी ही शामिल नहीं हैं, बल्कि मंदिर प्रशासन के कुछ अन्य अंदरूनी सेवादार, सुरक्षाकर्मी और बाहरी दलाल भी शामिल हो सकते हैं।

वैदिक अनुष्ठानों एवं भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित, स्वराभिषेक में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • श्री केशवानंद सरस्वती आश्रम ट्रस्ट एवं श्री दत्त माऊली भाविक मंडल द्वारा आयोजित श्रीदत्त देवालय अवधूत मंदिरम् के श्रीदत्तात्रेय मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के षष्ठम दिवस गुरुवार को वैदिक परंपरानुसार विविध धार्मिक अनुष्ठान अत्यंत श्रद्धा एवं विधि-विधान से संपन्न हुए। प्रात:काल एककोणी कलश स्थापना, स्थिर प्रतिष्ठा, स्थापित देवताओं का पूजन, उद्वासन, अभिषेक, पूर्णाहुति तथा ब्राह्मण सम्मान सहित सभी धार्मिक विधान सम्पन्न हुए।

दिनभर मंदिर परिसर में भगवान श्रीदत्तात्रेय के दर्शन एवं पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। इस अवसर पर परम पूज्य दंडी संन्यासी प.पू. पुरुषोत्तम आश्रम स्वामी (इंदौर),

प.पू. रामानंद तीर्थ स्वामी (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) एवं प.पू. कृष्णानंद सरस्वती स्वामी (गाडरवाड़ा) ने भक्तों को दर्शन देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। श्रद्धालुओं ने तीनों संतों का आशीर्वचन प्राप्त कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। सायंकाल आयोजित स्वराभिषेक कार्यक्रम ने महोत्सव को भक्ति और संगीत की अनुपम ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया। प्रसिद्ध भजन गायक पं. सुनील मसुरकर ने मराठी एवं हिन्दी भजनों की ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों से हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उनके साथ रवि किल्लेदार (हारमोनियम), मनोज पवार (तबला), प्रखर विजयवर्गीय (पखावज) तथा विश्वास कलमकर (झांझ) ने उत्कृष्ट संगत प्रदान की। भजनों के बीच संपूर्ण परिसर भगवान श्रीदत्तात्रेय के जयघोष एवं 'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा' के गगनभेदी उद्घोष से गुंजायमान रहा। महोत्सव के संयोजकों ने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित वैदिक अनुष्ठान, संतों का पावन सान्निध्य एवं स्वराभिषेक जैसे सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन रहे हैं। सनातन संस्कृति, वेद परंपरा एवं भक्ति संगीत के इस महायज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।

न्यूज ब्रीफ

एक दिन में ऊर्जस एप ने की 298 उपभोक्ताओं की मदद

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का ऊर्जस एप मौसमी कारणों से आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने पर बिजली पुन: चालू कराने में कारगर साबित हो रहा है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि ऊर्जस एप पर फ्यूज ऑफ कॉल यानि बिजली बंद होने की शिकायत आने पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता हैं। चौहान ने बताया कि इंदौर शहर के सबस ज्यादा 225 उपभोक्ताओं ने आपूर्ति संबंधी मदद ली। उज्जैन के 20 उपभोक्ताओं ने इसी तरह खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, नीमच, शाजापुर के उपभोक्ताओं ने भी बिजली चालू करने में ऊर्जस एप की मदद ली ।

संभागायुक्त ने धार जिले का किया दौरा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● संभागायुक्त इंदौर डॉ. सुदाम खाड़े ने गुरुवार को धार जिले का दौरा कर प्रदेश की औद्योगिक एवं कृषि विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने एक ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित किए जा रहे महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का अवलोकन कर वहां चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं बदनावर विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में आधुनिक उद्यानिकी एवं संरक्षित खेती के नवाचारों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर संभागायुक्त ने झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड का व्यापक भ्रमण कर कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया।

कैनन ने ईओएस आर6वी लॉन्च किया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अग्रणी डिजिटल इमेजिंग कंपनियों में से एक, कैनन इंडिया ने अपनी लेटेस्ट प्रोफेशनल कैमरा किट लॉन्च की है। इस किट में ईओएस आर6वी फुल फ्रेम कैमरा और आरएफ 20-50 एफ4एल आईएस यूएसएम लेंस है। यह बिल्ट इन पॉवर जूम के साथ कैनन का पहला फुल-फ्रेम प्रोफेशनल-ग्रेड एल-सीरीज लेंस है।

वर्षाकाल में जलजमाव को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर ने ली बैठक

लापरवाही पाये जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर में वर्षाकाल के दौरान जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने वर्षा के दौरान जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी स्थिति में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने। लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उक्त समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के संयुक्त दल बनाये जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी, अपर कलेक्टर रोशन राय सहित नगर निगम, यातायात पुलिस, एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी नालों, चैनलों, तालाबों के आसपास तथा जलभराव वाले स्थलों की साफ-सफाई तत्काल की जाए ताकि जलभराव व ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने । साथ ही स्टॉर्म वॉटर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम की सफाई भी प्राथमिकता से की जाए, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति निर्मित न हो।

साथ ही कलेक्टर वर्मा ने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि आवश्यक पैचवर्क, डामरीकरण एवं सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि बारिश के दौरान गड्ढों एवं जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप भी किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए तथा जहां भी पानी भरने की समस्या हो, वहां तत्काल पंप लगाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए।

फीस बढ़ोतरी, भारी जुर्माना और एफिडेविट की शर्त, डीएवीवी हॉस्टल के छात्र परेशान!

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● यदि हर साल डीएवीवी हॉस्टल की फीस में लगभग 10% की बढ़ोतरी की जाती है, तो यह स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन छात्रों को इसकी जानकारी पहले से दी जानी चाहिए, ताकि वे समय रहते अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर सकें। इस बार फीस 22,500 से बढ़ाकर 24,750 कर दी गई, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना या नोटिस छात्रों तक नहीं पहुंचाया गया। जब हम फीस जमा करने गए, तभी हमें पता चला कि फीस बढ़ चुकी है। ऐसे में अचानक अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो गया।

इसके बाद जिन छात्रों ने घर जाने से पहले अपने कमरे पर ताला लगाया था, उन पर जुर्माना लगा दिया गया। हर साल यह जुर्माना 300 प्रति छात्र होता था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 2,500 प्रति छात्र कर दिया गया है। यानी जुर्माने में लगभग 733% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यदि एक कमरे में दो छात्र रहते हैं, तो दोनों को 2,500-2,500, यानी कुल 5,000 का जुर्माना देना पड़ रहा है।

कमरे खाली करवाने का कारण रिनोवेशन बताया गया था, लेकिन अब तक कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। इसके बावजूद छात्रों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही, छात्रों से एक एफिडेविट (शपथ पत्र) भी मांगा जा रहा है, जिसमें यह लिखवाया जा रहा है कि वे भविष्य में घर जाते समय अपने कमरे पर ताला लगाकर नहीं जाएंगे। इन सभी कारणों से डीएवीवी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जो व्यक्ति सप्त व्यसन में नहीं लगा वही सच्चा श्रावक है - सम्बुद्ध सागर महाराज

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री सम्बुद्ध सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश श्री महावीर जिनालय संगम नगर में हुआ। रास्ते भर समाज जनों ने मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया एवं आरती उतारी। मुनि श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि सभी लोग मिलकर रहो तथा सभी जीवों के प्रति वात्सल्य एवं क्षमा का भाव रखो। समाज भी एक परिवार है, एक दूसरे में दोष मत देखो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब भी आप कहीं 28 मूल गुणों के धारी दिगंबर मुनिराज को देखो तो, वहां नमन करो। यह मत देखो की किस संघ के मुनिराज हैं। संघ मायने नहीं रखता चर्या तथा दिगंबर मुद्रा मायने रखती है। पंथ वाद से मत जूझो। मुनि श्री सम्बुद्ध सागर जी महाराज ने कहा कि एक अच्छे श्रावक की पहचान है मद्द, मांस, मधु का त्याग होना। जो व्यक्ति सप्त व्यसन में नहीं लगा, वही सच्चा श्रावक है।

गौ मांस के अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में मांस का अवैध रूप से क्रय विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने उक्त दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जिन कुख्यात आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया गया है उनमें इमरान पिता अनवर खटखट एवं मोहम्मद हाशिम पिता मोहम्मद याकुब, दोनों निवासी बंडाबस्ती, थाना महू शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर लंबे समय से मारपीट, धमकी, गोवंश वध, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। 29 मई 2026 को बंडाबस्ती में गोवंश वध के मामले में दर्ज अपराध के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। दोनों आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है।

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शिप्रा घाट का किया निरीक्षण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को सांवेर क्षेत्र के बूढ़ी बरलाई स्थित शिप्रा नदी के निर्माणाधीन घाट का निरीक्षण कर सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के समुचित विकास पर विशेष बल दिया।

महू के प्रभारी प्राचार्य प्रभाकर शुक्ला के सेवानिवृत होने पर विद्यालय परिवार ने विदाई पार्टी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पीएमश्री शासकीय कन्या उमावि महू में प्रभाकर शुक्ला प्रभारी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति पर संस्था द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व प्राचार्य आर एस नग्रेश, परिवार के सदस्य अर्चना शुक्ला, डॉक्टर नेनू शर्मा शशांक शर्मा,ऋषि शुक्ला,प्रमोद कुमार शुक्ला, सुनील जोशी और एडवोकेट आशीष कानूनगो बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन सहयोगी एवं शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी दिनेश परमार, सुरेश उजले, प्राचार्य श्रीमती तनुजा होलकर, सुंदरलाल गाड़गे, सुश्री सुशीला माने, मधुबाला वर्मा, समस्त स्टाफ के साथीगण की उपस्थिति में संपन्न हुआ प्रशस्ति पत्र का वाचन सुरेंद्र मेहरा, कार्यक्रम का संचालन आशा अड़गले और आभार मीनाक्षी सूत्रकार ने माना।

बिजली कंपनी में रिक्त पद नहीं, फिर भी कराई भर्ती परीक्षा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पिछले एक वर्ष में 350 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के इंतजार में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बिजली कंपनी कह रही है कि उसके पास पद नहीं हैं।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2024 में वर्ग-3 के 818 पदों पर भर्ती निकाली। परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हुआ, दस्तावेज सत्यापन भी पूरा हो गया। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद करीब 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन 350 से अधिक चयनित अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अब न नई नौकरी मिल रही है और न ही पुरानी बची। सवाल उठता है कि यदि पद नहीं थे तो भर्ती निकाली ही क्यों गई?

हाईकोर्ट के दखल के बाद 250 लोगों को मिली नौकरी- मार्च 2025 में परीक्षा हुई और उसी साल 28 मई को पहला परिणाम घोषित किया गया। हालांकि, महज दो घंटे बाद परिणाम वेबसाइट से हटा लिया गया। विभाग ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। दो दिन बाद 30 मई को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसके आधार पर 23 और 24 जून 2025 को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया।

सामान्यत: दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच जाती है, इसलिए अभ्यर्थियों को भरोसा था कि अब जॉइनिंग मिल जाएगी। इसी बीच उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसके बाद करीब 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन 350 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को यह कहकर रोक दिया गया कि अब विभाग के पास रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं।

श्याम सुंदर यादव का जन्मदिन मनाया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कांग्रेस के समर्पित स्तंभ और जीवनपर्यंत श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रखर श्रमिक नेता श्याम सुंदर यादव का 85वां जन्मदिन 'इन्दौर समाचार' परिसर में पूरे जोश, उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपने चहेते नेता को बधाई देने के लिए श्रमिक कामगारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा।

गुजरात से बिना जीएसटी बिल लिए इंदौर पहुंचे दो ट्रक, पुलिस ने पकड़कर जीएसटी विभाग के हवाले किए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में बिना वैध जीएसटी दस्तावेजों के बड़ी मात्रा में माल लाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रकों को जब्त कर जीएसटी विभाग के हवाले कर दिया है। अब विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है।

पुलिस के अनुसार, परदेसीपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात के सूरत से आए दो ट्रक थाना क्षेत्र स्थित एक किराना दुकान पर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री और अन्य सामान लेकर पहुंचे हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि माल के साथ जीएसटी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सूचना मिलते ही परदेसीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। पूछताछ के दौरान ट्रक चालकों से माल से संबंधित जीएसटी बिल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। हालांकि चालकों द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, वे अधूरे पाए गए और उनमें कई आवश्यक जानकारियां भी नहीं थीं।

विदेश जाने की चाहत बढ़ने से छोटे ज़िलों में भी पासपोर्ट बनवाने की होड़

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्य प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने का चलन अब सिर्फ़ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहा है। छोटे ज़िले पासपोर्ट आवेदनों के मामले में तेज़ी से बढ़ते केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि नौकरी, उच्च शिक्षा और पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसी ट्रेंड को देखते हुए, राज्य ने 2025 में रिकॉर्ड 2.78 लाख पासपोर्ट जारी किए, जो 2022 की तुलना में लगभग 47% ज़्यादा हैं।

उमरिया, डिंडोरी, धार, देवास, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, भिंड और जबलपुर जैसे ज़िलों में नए आवेदनों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जो यह दिखाता है कि विदेश जाने की चाहत भोपाल और इंदौर से कहीं आगे तक फैल रही है।

पासपोर्ट जारी करने की संख्या लगातार बढ़ी है: 2022 में 1.89 लाख से बढ़कर 2023 में 2.05 लाख, 2024 में 2.59 लाख और 2025 में 2.78 लाख हो गई। अब हर महीने औसतन 20,000 से 30,000 पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जबकि रोज़ाना अपॉइंटमेंट बुकिंग 2022 में लगभग 1,700 से बढ़कर अब करीब 2,700 हो गई है।

राज्य में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट जारी करने के मामले में इंदौर सबसे आगे है, और उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की मिलाकर रोज़ाना अपॉइंटमेंट क्षमता लगभग 1,800 है, जिसमें इंदौर पीएसके लगभग 1,000 और भोपाल पीएसके करीब 800 अपॉइंटमेंट संभालता है।

अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती मांग को इन सेंटर्स और राज्य भर में फैल रहे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के नेटवर्क के ज़रिए पूरा किया जा रहा है।

भोपाल के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, शितांशु चौरसिया ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश से विदेश यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। नए आवेदनों के अलावा, पासपोर्ट दोबारा जारी करवाने वालों की संख्या में भी काफी इज़ाफ़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के विस्तार से दूर-दराज़ और बाहरी इलाकों के लोगों के लिए पासपोर्ट सेवाएँ आसान हो गई हैं, जिन्हें पहले लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे आवेदनों की संख्या बढ़ने में मदद मिली है।'

डीएनए से हुई इंदौर के यात्रियों की पहचान, सुबह दौसा से इंदौर आएंगे दोनों शव

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राजस्थान के दौसा में हुए भीषण बस हादसे में जान गंवाने वाली इंदौर की भूमि और निर्मला गुप्ता के शव डीएनए जांच के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। दोनों के शव पूरी तरह जल जाने के कारण पहचान डीएनए सैंपल से की गई। राजस्थान के दौसा में हुए बस हादसे में मृत इंदौर की भूमि और निर्मला के शव दौसा प्रशासन ने उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। दोनों के शव बस हादसे में पूरी तरह जल चुके थे। इस कारण शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर जांच की गई। इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शवों को लेकर रात में दौसा से रवाना हो गए। सुबह इंदौर पहुंचने के बाद दोनों की शव यात्रा निकलेगी।

इंदौर के मेघदूत नगर में रहने वाली भूमि के पिता बुधवार को इंदौर से रवाना हुए थे। शाम को उनका डीएनए सैंपल लिया गया और पहचान की पुष्टि होने के बाद भूमि का शव उन्हें सौंप दिया गया। भूमि अपनी सहेलियों दिशा और लिसा के साथ घूमने गई थी। हादसे में दोनों घायल हुई हैं, लेकिन उनके परिजन उन्हें दौसा से इंदौर ले आए। अब उनका इलाज इंदौर में ही होगा।

इंदौर की निर्मला गुप्ता का अंतिम संस्कार शुक्रवार को रीजनल पार्क मुक्तिधाम में होगा। हादसे के बाद ग्वालियर निवासी उनकी बेटी और दामाद दौसा चले गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में उनकी एक बेटी डिप्टी कलेक्टर है। वह इंदौर आ गई थी।

इंदौर स्वच्छता मॉडल से प्रभावित हुए नीदरलैंड के काउंसलर जनरल

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नीदरलैंड के काउंसल जनरल नबील ताउआती दो दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निज निवास पर महापौर से मुलाकात की। इसके बाद शहर के विश्वप्रसिद्ध स्वच्छता मॉडल, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा कचरा प्रसंस्करण (वेस्ट प्रोसेसिंग) की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं को डिटेल में जाना।

दौरे के दौरान काउंसल जनरल ने इंदौर में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि इंदौर ने प्रभावी प्रबंधन और तकनीक के समन्वय से स्वच्छता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नीदरलैंड के पास अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता उपलब्ध है।

खाली प्लॉट बना दिया मेडिकल कचरे का डंपिंग ग्राउंड!

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, निगम ने ठोका जुर्माना

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर को स्वच्छता में नंबर-1 बनाने के दावों के बीच एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है। लोगों की जिंदगी बचाने का दावा करने वाले अस्पताल प्रबंधन ने ही स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरे में डालते हुए मेडिकल वेस्ट खाली प्लॉट पर फेंक दिया। मामला सामने आने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल पर जुर्माना लगाया।

जानकारी के अनुसार सी-21 मॉल के पीछे स्थित खाली प्लॉटों में बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट पड़े होने की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो अस्पताल से निकला जैव-चिकित्सा कचरा खुले में बिखरा मिला। यह कचरा संक्रमण फैलाने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए स्पष्ट नियम और व्यवस्था मौजूद है, तब अस्पताल प्रबंधन ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है? यदि समय रहते शिकायत नहीं होती तो यह खतरनाक कचरा किसी बड़े संक्रमण का कारण भी बन सकता था। नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माना लगाते हुए भविष्य में ऐसी हरकत दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही शहर के अन्य अस्पतालों को भी साफ संदेश दिया गया है कि मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाने वाले अस्पताल यदि खुद ही मेडिकल कचरे को सड़कों और खाली प्लॉटों में फेंकेंगे, तो शहरवासियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, शुक्रवार 03 जुलाई 2026

न्यूज ब्रीफ

जिला अस्पताल में निकला सांप, मरीजों में फैला डर

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● जिला अस्पताल के एक्स-रे विभाग में गुरुवार सुबह सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। सुबह स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा तो फर्श पर एक सांप रेंगता दिखाई दिया। इसे देखकर मरीज और कर्मचारी घबरा गए। सांप देखते ही पास रखी एक अलमारी में घुस गया। इससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। घटना की सूचना तुरंत अस्पताल के गार्डों को दी गई। सूचना मिलते ही गार्ड मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। सुरक्षा के लिए एक्स-रे विभाग में मरीजों और अन्य लोगों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गार्डों ने अलमारी में छिपे सांप को बाहर निकालने के लिए करीब आधे घंटे तक प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद गार्ड ने सांप को सुरक्षित पकड़कर एक थैले में रखा। इसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। समय रहते रेस्क्यू होने से कोई जनहानि नहीं हुई और अस्पताल की व्यवस्था सामान्य हो गई।

अतिशय क्षेत्र मक्सी में आचार्य प्रसन्न सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●जैन धर्म के प्रखर प्रवक्ता, तपस्वी संम्राट एवं सरलता की मूर्ति अंतरमना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज बिहाररत का आज अतिशय क्षेत्र मक्सी में भव्य मंगल प्रवेश सम्पन्न हुआ। नगर की सीमा से प्रारंभ हुई शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु ' 'आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय' के उद्घोष करते हुए चल रहे थे। फेडरेशन के मिडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू ने बताया कि ट्रस्ट एवं फेडरेशन , दिगंबर जैन समाज समाजिक सांसद के पदाधिकारी रहे उपस्थित मंगल प्रवेश के अवसर पर मक्सी ट्रस्ट कमेटी, इन्दौर-उज्जैन-देवास सहित विभिन्न स्थानों से पधारे दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पदाधिकारी एवं इन्दौर दिगम्बर जैन समाज सामाजिक संसद के कीर्ति स्तंभ के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। भव्य मंगल प्रवेश आगवानी में ये गणमान्य रहे शामिल महावीर ट्रस्ट, अष्टापद बद्रीनाथ ट्रस्ट, दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन एवं दिगम्बर जैन समाज सामाजिक संसद के प्रतिनिधि गण प्रमुख रूप से शामिल हुए। दद्दू ने बताया कि समाज श्रेष्ठी अमित कासलीवाल, आदित्य कासलीवाल, आनंद गोधा, एम. के. जैन, मनोहर झांझरी, अश्विन कासलीवाल, सुशील पांड्या, दिलीप पाटनी कमलेश कासलीवाल, संजय पापडीवाल, राकेश विनायका आदि ने महाराज श्री का पाद प्रक्षालन कर, शास्त्र-भेट एवं मंगल आरती कर अपने जीवन को धन्य माना।

पुलिसकर्मियों को बड़ी सुविधा, मोबाइल से करें छुट्टी के लिए आवेदन

भोपाल (एजेंसी) ● पुलिस कर्मियों की सेवा प्रबंधन प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में 1 जुलाई 2026 से इलेक्ट्रनिक ह्यूमन रिर्सोस मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एचआरएमएस) लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है।

इस सिस्टम के जरिए प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीव की स्वीकृति और अपडेट की जानकारी मिल पाएगी। इससे प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध हो जाएगी।

जुलाई 2025 से ई-एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग शुरू

मध्यप्रदेश पुलिस ने पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में जुलाई 2025 से ई-एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग शुरू की थी। इसके तहत सेवा पुस्तिकाओं (सर्विस बुक) को स्कैन कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। एमपीएसईडीसी की मदद से एक लाख से अधिक सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की गई। फिलहाल प्रदेश के करीब 1 लाख पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ई-एचआरएमएस से जुड़ चुके हैं।

सेवा संबंधी सभी महत्वपूर्ण आदेशों को सुरक्षित रखने के लिए 23 मार्च 2026 से ई-एचआरएमएस ऑर्डर बुक मॉड्यूल भी शुरू किया गया। अब सेवा पुस्तिका से जुड़े सभी जरूरी आदेश पोर्टल पर डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से देखा जा सकेगा।

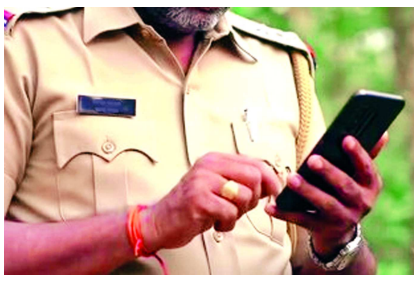

लीव मॉड्यूल 120 पुलिस इकाइयों में लागू

ई-लीव मॉड्यूल को पहले एससीआरबी, कार्मिक शाखा, विशेष शाखा, रेल पुलिस भोपाल और 25वीं वाहिनी भोपाल में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था। वहां से मिले सुझावों के आधार पर इसमें सुधार किए गए। इसके बाद अब इसे प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में लागू कर दिया गया है।

ये है छुट्टी के आवेदन की प्रक्रिया

अब पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-एचआरएमएस पोर्टल या ई-एचआरएमएस मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद संबंधित लीव क्लर्क उसे सक्षम अधिकारी के पास ऑनलाइन भेजेगा। अधिकारी भी ऑनलाइन ही छुट्टी मंजूर या अस्वीकार करेंगे। कर्मचारी अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन की पूरी स्थिति देख सकेंगे। इससे छुट्टी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। गौरतलब है कि, ई-एचआरएमएस का ई-लीव मॉड्यूल फिलहाल मध्यप्रदेश शासन के कुछ ही विभागों में लागू है।

देपालपुर संकल्प रिटेल स्टोर का सोयाबीन बीज निकला खराब

सोयाबीन बोनी के बाद बीज जमीन में ही सड़ गया

निलेश चौहान (94250-77209)

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

देपालपुर क्षेत्र के किसान मनोहर गेहलोत द्वारा खरीदे गए सोयाबीन बीज के अंकुरण नहीं होने का गंभीर मामला सामने आया है। किसान द्वारा संकल्प रिटेल स्टोर, देपालपुर से कुबेर सीड्स एंड बायोटेक कंपनी का सोयाबीन बीज (किस्म JS-2303) खरीदा गया था, जिसकी बुवाई करने के बाद भी खेत में अंकुरण नहीं हुआ। किसान के अनुसार खेत में पर्याप्त नमी एवं अनुकूल मौसम होने के बावजूद बीज जमीन में सड़ गया, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

किसान ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर बीज विक्रेता एवं कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई तथा हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। शिकायत के साथ बीज की पैकिंग, खरीद बिल एवं अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। यह मामला बीजों की गुणवत्ता, प्रमाणन प्रक्रिया तथा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि आदानों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के चंदन सिंह बड़वाया ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यदि जांच में बीज की गुणवत्ता में कमी या कंपनी एवं विक्रेता की लापरवाही सिद्ध होती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा प्रभावित किसान को हुए आर्थिक नुकसान का उचित मुआवजा तत्काल दिलाया जाए।

संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में लगातार किसानों को खराब बीज, खाद एवं कृषि आदानों की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों बर्बाद हो रही हैं। यदि प्रशासन द्वारा इस मामले में शीघ्र एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे साथ ही सोयाबीन बीज की गुणवत्ता की जांच की जाए।

खराब सड़क से परेशान लोगों का चक्काजाम

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● खातेगांव के मेघनाथ चौराहा-तिवड़िया रोड पर गुरुवार दोपहर स्थानीय निवासियों ने खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की जर्जर हालत, जलभराव, धंसने के खतरे और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद जेसीबी मशीन बुलाकर सड़क पर जमा मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्षद संगीता यादव, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव, जनपद उपाध्यक्ष मनीष पटेल और किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश बरड़ ने किया। इसमें स्थानीय निवासियों के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। स्कूल से बच्चों को लेने पहुंचे कई अभिभावक भी सड़क की खराब स्थिति से नाराज होकर प्रदर्शन में शामिल हो गए।

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यह मार्ग तीन बड़े स्कूलों को जोड़ता है और प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी तथा 30 से अधिक गांवों के लोग खातेगांव आने-जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जल-जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई से निकली मिट्टी सड़क पर फैली हुई है, जिससे दोपहिया वाहन लगातार फिसल रहे हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं।

कार और मिनी ट्रक की टक्कर, दूध व्यापारी की मौत

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● देवास जिले के हाटपीपल्या क्षेत्र में नेवरी-चापड़ा मार्ग पर बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नलकी हनुमान मंदिर के पास कार और मिनी ट्रक की आमने-सामने टक्कर में कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नेवरी निवासी 42 वर्षीय राजेश जाट के रूप में हुई है। वे दूध व्यापारी थे। पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार देर रात करीब 3 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी ट्रक के आगे के दोनों पहिए निकल गए और उसकी दिशा बदल गई। वहीं, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार के एयरबैग भी खुल गए थे।

सीएमएचओ ने ली समीक्षा बैठक

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग में सीएमएचओ डॉ. अनीता सिंगारे, डीपीएम डॉ. वीरेंद्र रघुवंशी और बीएमओ डॉ. नितिन श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए मेडिकल हब और एक्स-रे सुविधा शुरू करने की मांग की। बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सीएचओ, एएनएम और एमपी डब्ल्यू के लक्ष्यों की समीक्षा की गई।

स्कूली बसों के फिटनेस का सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●स्कूली बसों के फिटनेस सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में इनका रिकॉर्ड शो नही हो रहा है। सुधार कराए बगैर संचालन अवैध करार दिया जा रहा है। स्कूल शुरू होने के पहले ही इस समस्या के चलते कुछ स्कूली बसें तो चल ही नही पाई। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को स्कूल छोड़ने व लाने जाना पड़ा। इधर, परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल बस संचालकों को स्पष्ट कह दिया है कि वे किसी भी प्रकार की रिस्क न लें और न ही उन्हें मुश्किल में डाले। बस के फिटनेस को अपडेट करने के लिए वे शोरूम से फॉर्म नंबर 21-22 लेकर आए, ताकि उस जानकारी के आधार पर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सके। ऐसे में बुधवार को दिनभर में 20 बस संचालक ही ये दस्तावेज लाकर दे पाए। ये समस्या कुछ दिन पहले से हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई तक सुधार हो जाएगा।

अवैध हथियारों का नेटवर्क ध्वस्त, 5 तस्कर गिरफ्तार

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक ही रात में चार अलग-अलग जगह दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 14 देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले दो दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं।

जब्त सामग्री की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी निमाड़ क्षेत्र से हथियार लाकर देवास के अपराधियों को 15 से 25 हजार रुपए प्रति पिस्टल के हिसाब से बेचते थे। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने प्रेसवार्ता में बताया कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को लगातार मुखबिरों से सूचना मिल रही थी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्धमान और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। टीम ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अंकित रायकवार, साहिल वर्मा, इरफान शेख, अक्षय शिंदे और शुभम पांचाल को पकड़ा।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी निमाड़ क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर देवास लाते थे और यहां अपराधियों को बेचते थे। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले अंकित और साहिल को पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर हथियार खरीदने वाले तीन अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए।

11 पिस्टल बेचने की तैयारी में थे - जांच में पता चला कि बरामद 14 पिस्टलों में से 11 बिक्री के लिए तैयार थीं। आरोपी सुनसान जगहों पर ग्राहकों को बुलाकर डिलीवरी करते थे, ताकि किसी को भनक न लगे। कई बार आरोपी खुद निमाड़ जाकर हथियार लाते थे, जबकि कई बार सप्लायर सीधे देवास पहुंचते थे।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

देश की पहली नदी जोड़ो केन-बेतवा लिंक परियोजना कानूनन अवैध

भोपाल (एजेंसी) ● देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 'केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट' कानूनी और तकनीकी विवादों में घिर गया है। सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की कई अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं हुआ। इनमें प्रभावित परिवारों के रिहेबिलिटेशन की सबसे अहम शर्त अब भी अधूरी है। नियमों के अनुसार, जरूरी शर्तें पूरी न होने पर प्रोजेक्ट के लिए दोबारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेना पड़ता है। जिला प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि प्रभावित परिवारों का अब तक पूरा पुनर्वास नहीं हुआ। वहीं, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अहम सिफारिशों का भी पूरा पालन नहीं हुआ। इन हालातों में करीब 45 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोजेक्ट के कानूनी और तकनीकी विवादों को समझने के लिए भास्कर ने सरकारी दस्तावेजों की जांच की और एक्सपर्ट्स से बातचीत की। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बुंदेलखंड के जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए दौधन बांध बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का 6,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलमग्न होगा। इस पर्यावरणीय असर को देखते हुए प्रोजेक्ट को दो चरणों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस दी गई थी।

मई 2017 में स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लीयरेंस तो अक्टूबर 2023 में स्टेज-2 की मंजूरी मिली। दोनों चरणों में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़ी कई जरूरी शर्तें रखी गईं, जिनमें कई समान थीं। सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया है कि इन अनिवार्य शर्तों का पूर्ण पालन नहीं हुआ।

यही प्रावधान स्टेज-2 क्लीयरेंस (अक्टूबर 2023) में शर्त-2 के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के पश्चिम में 6,809 हेक्टेयर गैर-वन भूमि को वन क्षेत्र में शामिल करना था, जिसमें 6,017 हेक्टेयर भूमि को टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया जाना था। साथ ही, 3 अप्रैल 2024 तक प्रक्रिया पूरी कर इस भूमि को आरक्षित वन घोषित करना अनिवार्य था।

पत्रकार चंदू गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला गुप्ता का आकस्मिक निधन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री नागर चित्तौड़ा वैश्य महाजन समाज के समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार चंदू गुप्ता की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला गुप्ता (66) का निधन हो गया। वे डॉ. प्रियंका (मेडिकल ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर), मयंक (ज़ोनल मैनेजर, इंड्यूरेन्स, पुणे), दीपाश्री (संयुक्त कलेक्टर) की माताजी एवं डॉ. वरुण नीखरा (डेंटल सर्जन, ग्वालियर) एवं रोहित काशवानी (आईपीएस, एस.पी. विदिशा) की सासुजी थी और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चली गई हैं। श्रीमती निर्मला जीवन पर्यन्त धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही। मृत्यु के ठीक पहले वे चार धाम की यात्रा सम्पन्न कर हरिद्वार से इंदौर लौट रही थीं, इस दौरान दिल्ली-मुंबई राजमार्ग पर दौसा के निकट हुई भीषण दुर्घटना में गम्भीर चोट लगने से उनका निधन हो गया।

सम्पादकीय

गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर मंत्री पद जाएगा, सरकार फिर ला सकती है नया संविधान संशोधन

पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। देश की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के मसले पर लंबे समय से बहस चलती रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, ताकि सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पांच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था। इसमें कोई दोराय नहीं कि भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बढ़ता दखल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर कई बार ऐसे लोग भी चुनकर संसद या विधानसभाओं में आ जाते हैं, जिन पर जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप होता है। अक्सर सामने आने वाली रिपोर्ट में खासी संख्या में दागी जनप्रतिनिधियों के विधायिका में पहुंचने का ब्योरा होता है, जिस पर सभी दल चिंता जताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट न देने को लेकर किसी के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखती।

नई संवैधानिक सर्जरी : सत्ता से अपराध की सीधी विदाई

भारतीय राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सियों के लिए अब केवल जनादेश पर्याप्त नहीं रहेगा, बल्कि कानून की कसौटी पर खरा उतरना भी अनिवार्य होगा। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 (जो अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश किया गया) इसी नई व्यवस्था का संकेत देता है। इसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध में, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, लगातार तीस दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे इकतीसवें दिन पद छोड़ना होगा। इस्तीफा न देने पर उसका पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। यह संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर प्रहार है, जिसमें जेल से भी सत्ता संचालित होती रही। संदेश स्पष्ट है-लोकतंत्र में जनादेश सम्मान देता है, पर पद पर बने रहने का अधिकार अंतत: कानून और जनविश्वास ही तय करेंगे। इस विधेयक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने जवाबदेही को समय-सीमा से बांध दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित अवधि पूरी होते ही पद छोड़ना अनिवार्य होगा। मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल, प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सलाह न आने पर भी पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। अर्थात अब संवैधानिक व्यवस्था किसी राजनीतिक निर्णय की बंधक नहीं रहेगी। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के लिली थॉमस निर्णय की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसने दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता का सिद्धांत स्थापित किया था। रेप्रेज़ेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 पहले से दोषसिद्ध जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराता है, किंतु नया संशोधन जवाबदेही की शुरुआत दोषसिद्धि के बाद नहीं, बल्कि गंभीर मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत से ही कर देता है। यही इसे अब तक की व्यवस्थाओं से अलग और अधिक प्रभावी बनाता है।

यदि यह संशोधन प्रभावी ढंग से लागू हुआ, तो राजनीति की कार्यसंस्कृति बदल सकती है। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर इसका सीधा प्रहार होगा, क्योंकि गंभीर मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत अब केवल कानूनी संकट नहीं, बल्कि सत्ता से विदाई का कारण भी बन सकती है। इससे स्वच्छ छवि वाले नेतृत्व को अवसर मिलेगा, ईमानदार युवाओं का भरोसा बढ़ेगा और जनता का विश्वास मजबूत होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। शासन का ध्यान व्यक्तिगत मुकदमों से हटकर विकास और सुशासन पर केंद्रित रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह स्थायी दंड नहीं है; न्यायिक राहत मिलने पर पुनर्नियुक्ति संभव होगी। इसलिए यह व्यवस्था प्रतिशोध नहीं, बल्कि सार्वजनिक पद की गरिमा और जवाबदेही को सुरक्षित रखने का निवारक उपाय अधिक है। इसी कारण कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल लंबी न्यायिक हिरासत, बिना दोषसिद्धि के, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाने का आधार बन सकती है, जबकि न्याय का मूल सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानता है। विपक्ष और अनेक विधि विशेषज्ञों को आशंका है कि जांच एजेंसियों पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ने पर यह प्रावधान विरोधियों को सत्ता से हटाने का हथियार बन सकता है। विशेषकर विपक्ष शासित राज्यों में इससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसलिए इस संशोधन की वास्तविक कसौटी उसकी कठोरता नहीं, बल्कि निष्पक्ष और दुरुपयोग-मुक्त क्रियान्वयन होगी।

इस बदलाव का असर केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारों की स्थिरता पर भी पड़ेगा। छोटे बहुमत वाली सरकारों में यदि मुख्यमंत्री या कई मंत्री एक साथ पद छोड़ने को विवश हुए, तो सत्ता का संतुलन बदल सकता है और नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं। समर्थकों का तर्क है कि यदि किसी सरकार की स्थिरता गंभीर मामलों में जेल में बंद नेताओं पर टिकी है, तो ऐसी स्थिरता लोकतंत्र के हित में नहीं मानी जा सकती। इसलिए असली चुनौती सरकार बचाने की नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता बनाए रखने की है। आखिर लोकतंत्र केवल सरकारों के टिके रहने से नहीं, बल्कि जनता के अटूट विश्वास से मजबूत होता है।

यह विधेयक भारतीय राजनीति को दो खेमों में बांट चुका है और जेपीसी में इस पर बहस जारी है। सत्तापक्ष इसे भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानता है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर आघात बताता है। इसलिए संसदीय समिति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह सभी प्रावधानों की गहन समीक्षा कर दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि सांसद और विधायक विशेषाधिकार प्राप्त शासक नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह जनसेवक हैं। अत: यह संशोधन तभी सफल माना जाएगा जब जवाबदेही और न्याय का संतुलन बना रहे। वर्तमान में जेपीसी इस विधेयक की जांच कर रही है और जुलाई 2026 के मध्य तक रिपोर्ट पेश करेगी। इस संशोधन के दूरगामी प्रभाव राजनीति की कार्यसंस्कृति में भी दिखाई दे सकते हैं। दलों को स्वच्छ छवि और कानूनी रूप से निर्विवाद नेताओं को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे नए नेतृत्व के उभरने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जनता की अपेक्षाएं भी बदलेंगी। तब यह संशोधन केवल कानून नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का आधार बन सकता है। लेकिन यदि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता संदेह के घेरे में रही, तो यही व्यवस्था लोकतांत्रिक टकराव और राजनीतिक अविश्वास का कारण भी बन सकती है। अंतिम कसौटी कानून बनाने की नहीं, उसे निष्पक्षता से लागू करने की होती है। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक भी उसी परीक्षा से गुजरेगा। यदि इसका संतुलित और निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह स्वच्छ शासन, उत्तरदायी नेतृत्व और कानून की सर्वोच्चता का नया अध्याय लिखेगा। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग हुआ, तो यही कानून लोकतांत्रिक विवादों का केंद्र बन जाएगा। अंतत: लोकतंत्र की मजबूती कानूनों की संख्या से नहीं, उनके न्यायपूर्ण पालन से तय होती है। सत्ता क्षणिक है, पर लोकतंत्र तभी स्थायी रहता है, जब उसके सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भी कानून के समक्ष सामान्य नागरिक की तरह जवाबदेह हों।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'
शिक्षाविद्, बड़वानी (मप्र)

सड़क पर मौतों का असली कारण-संस्कारहीनता नियम तोड़ना अपराध नहीं, संस्कार की विफलता है

भारत की सड़कों पर हर दिन औसतन 500 लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आँकड़ा केवल प्रशासनिक विफलता का नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संस्कारों की कमी का आईना है। 2024 में भारत में 4.88 लाख दुर्घटनाएँ और 1.8 लाख मौतें दर्ज हुईं। इनमें से लगभग 70% दुर्घटनाएँ ओवरस्पीडिंग के कारण थीं। दो-पहिया वाहनों में 46% मौतें और पैदल यात्रियों में 20% मौतें दर्ज हुईं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 18-45 वर्ष आयु वर्ग में 66% मौतें हुईं-यानी देश की सबसे उत्पादक पीढ़ी सड़क पर खत्म हो रही है।

वैश्विक स्तर पर WHO के अनुसार, 5-29 वर्ष आयु वर्ग में सड़क दुर्घटनाएँ मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। हर वर्ष लगभग 1.19 मिलियन लोग सड़क पर अपनी जान गंवाते हैं। यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आर्थिक बोझ भी है—निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दुर्घटनाएँ GDP का 2-6% तक नुकसान करती हैं।

अपराध नहीं, संस्कार का प्रश्न- हमारे समाज में यातायात नियम तोड़ना अपराध नहीं, बल्कि 'स्मार्टनेस' माना जाता है। पुलिस को चकमा देना, लालबत्ती पार करना या बिना हेलमेट तेज़ रफ्तार से निकल जाना मित्र मंडली में शौर्यगाथा की तरह सुनाया जाता है। यह मानसिकता ही दुर्घटनाओं का मूल कारण है। जब तक हम नियम उल्लंघन को अपराध और पापकर्म की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी कानून या दंड कारगर नहीं होगा।

परिवार: प्रथम विद्यालय- बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। यदि माता-पिता सीटबेल्ट नहीं बाँधते, हेलमेट नहीं पहनते, या ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो बच्चा उसे सामान्य व्यवहार समझता है। परिवार को यह स्वीकारना होगा कि यातायात नियम पालन संस्कार देना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी परिवार अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनाना चाहता; अत: यह संस्कार घर से ही शुरू होना चाहिए।

धर्म और नैतिकता का अंकुश- धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं की भूमिका यहाँ निर्णायक है। यदि वे यातायात नियमों के उल्लंघन को पापकर्म घोषित करें और नियम पालन को धार्मिक-नैतिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करें, तो समाज में गहरी चेतना उत्पन्न होगी। धर्म और नैतिकता ही वह अंकुश है जो मनुष्य को अपराधी बनने से रोकता है।

नीति और समाज का समन्वय- सरकार की रणनीति में प्रबंधन शामिल नहीं है लेकिन शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल (4श्वह्य) शामिल हैं। पर शिक्षा का घटक तब तक अधूरा है जब तक परिवार और धर्म इसमें सक्रिय भागीदार न बनें। स्कूलों में यातायात पाठ्यक्रम, माता-पिता-शिक्षक कार्यशालाएँ, और धार्मिक मंचों पर सुरक्षा संदेश—ये सभी उपाय मिलकर ही वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

व्यवहारिक प्रस्ताव

- **परिवार अनुबंध:** घर में लिखित नियम और उल्लंघन पर सुधारात्मक दायित्व।
- **धार्मिक उपदेश:** मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरिजाघर में सड़क सुरक्षा को नैतिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करना।
- **स्कूल-समुदाय कार्यशालाएँ:** बच्चों और माता-पिता को साथ लेकर प्रशिक्षण देना।
- **सकारात्मक प्रोत्साहन:** नियम पालन करने वाले परिवारों को सार्वजनिक मान्यता देना।

'सड़क पर नियम पालन करना केवल कानूनी कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन-धर्म है।' 'यदि हर परिवार यह संकल्प ले कि वह अपने बच्चों को अपराधी नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाएगा, तो ही सड़क पर हो रहे हाहाकार को रोका जा सकेगा।'

राजकुमार जैन, यातायात प्रबंधन विशेषज्ञ

आंचलिक

चार पंचायतों की जमीन हस्तांतरण पर हाईकोर्ट की रोक

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● सरदारपुर क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों की भूमि नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करने के मामले में ग्रामीणों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इंदौर खंडपीठ ने हनुमंतियाकाग, कचनारिया, टांडाखेड़ा और बोदली ग्राम पंचायतों की भूमि हस्तांतरण संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। गुरुवार को इन चारों ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में सरदारपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम सलोनी अग्रवाल को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की। ग्रामीणों ने न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, वे प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित किए जाने का पहले से विरोध कर रहे थे। इस संबंध में कलेक्टर और एसडीएम को कई बार ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायालय ने 30 जून को भूमि हस्तांतरण के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करने वाला है। उन्होंने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन से इसका पूरी गंभीरता से पालन करने की अपील की।

10 लाख नए किसान जुड़ेंगे सहकारिता से, 3 लाख ऋण सालभर में चुकाने की सुविधा - महेंद्रसिंह

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्रसिंह यादव गुरुवार को खरगोन पहुंचे। उन्होंने यहां किसान सदस्यता कार्ड और विभिन्न हितग्राही योजनाओं का लाभ वितरित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि सहकारिता के माध्यम से 10 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा और किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा, जिसे साल में एक बार चुकाया जा सकेगा। यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। सहकारिता से 10 लाख नए किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 7 लाख नए किसान जोड़े जा चुके हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कपास मंडी परिसर में प्रशासक यादव ने जिला सहकारी बैंक के सहकारिता सदस्यता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सहकारिता सदस्यों और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में सांसद गजेंद्रसिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, खरगोन बैंक की सीईओ संध्या रोकड़े सहित कई सहकारी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रशासक यादव ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सहकारिता को खत्म करने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करा रही है, जबकि पूर्व में यह ऋण 18 प्रतिशत ब्याज पर मिलता था। अब किसानों को छह-छह माह में ऋण चुकाने के बजाय साल में एक बार ऋण अदायगी की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समय के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे।

पंचायत विभाग के आदेश में खरगोन बना निमाड़ संभाग, खंडवा की मांग के बीच ट्रेनिंग शेड्यूल में खरगोन को मुख्यालय का दर्जा

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● मध्य प्रदेश में प्रस्तावित निमाड़ संभाग के मुख्यालय को लेकर चल रही खींचतान के बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक आदेश ने नई चर्चा छेड़ दी है। विभाग ने जल जीवन मिशन की ट्रेनिंग के लिए जारी शेड्यूल में खरगोन को संभाग मुख्यालय माना है। इससे खंडवा को मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालानालय ने संभाग स्तर पर होने वाले जल जीवन मिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम जारी किया है। वर्तमान में निमाड़ के चारों जिले इंदौर संभाग का हिस्सा हैं। हालांकि, नए आदेश में मंत्रालय ने प्रशासनिक सहूलियत को देखते हुए इंदौर संभाग के खरगोन और जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा को नए संभाग का दर्जा दिया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं के संधारण, संचालन और प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर संभाग में अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। खरगोन मुख्यालय पर यह ट्रेनिंग 8 जुलाई को आयोजित होगी। इसमें सीईओ जिला पंचायत, अतिरिक्त सीईओ, मनरेगा के परियोजना अधिकारी और पंचायत समन्वयक अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अफसर शामिल होंगे। निमाड़ संभाग का मुख्यालय खंडवा को बनाने के लिए शहर में सियासी संघर्ष जारी है। दो दिन पहले पंधाना विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता छाया मोरे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से दोबारा मुलाकात करने की बात कही थी। इस बीच कांग्रेस भी लगातार भाजपा को घेर रही है। मंगलवार को शहर कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें खंडवा को ही संभागीय मुख्यालय बनाने की प्रमुखता से मांग की गई है।

भेरूघाट पुल पर मरम्मत, वाहनों की लगी कतार

दैनिक इंदौर संकेत

धामनोद ● भेरूघाट स्थित अजनार नदी पुल पर मरम्मत कार्य के कारण जाम लग गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्री-मानसून निरीक्षण में पुल के एक्सपेंशन जॉइंट में तकनीकी खराबी पाई गई थी, जिसे सुरक्षा कारणों से बदलना अनिवार्य था। चार दिन पहले मरम्मत की गई थी, लेकिन 1 जुलाई को एक वाहन के क्षतिग्रस्त हिस्से पर चढ़ जाने से दोबारा मरम्मत करनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत में माइक्रो कंक्रीट जैसी विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। इस सामग्री को मजबूत होने में 3 से 6 दिन का समय लगता है। सुरक्षा कारणों से इस दौरान उस हिस्से पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते पुल की एक लेन बंद रखी गई है। एक्सपेंशन जॉइंट के समय से पहले क्षतिग्रस्त होने से पुल के स्लैब को नुकसान पहुंच सकता है और गंभीर दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। वर्तमान में, पुल की एक लेन से दोनों दिशाओं का यातायात नियंत्रित किया जा रहा है। मानपुर, धामनोद और किशनगंज पुलिस के साथ हृ्रद्ब, एम्बुलेंस, क्रेन, पेट्रोलिंग और रेस्क्यू टीमें 24 घंटे मौके पर तैनात हैं। इस मरम्मत कार्य के कारण यात्रियों को असुविधा और जाम का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि यदि मरम्मत कार्य सामान्य गति से चलता रहा, तो 4 जुलाई तक दोनों ओर का यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

बायपास निर्माण से खेतों में भरा पानी, किसान आंदोलन की धमकी दे रहे

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● राष्ट्रीय राजमार्ग 347सी पर भीलगांव-डोंगरगांव रोड पर बन रहे बायपास के कारण किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर गया है। किसानों का आरोप है कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि निर्माण कंपनी ने सड़क के दोनों ओर पर्याप्त नालियां और क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। किसान राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि कंपनी ने पांच से सात फीट ऊंची सीमेंट-कंक्रीट की दीवार बनाकर उसके पीछे 10 से 12 फीट तक मुरूम भर दी है। इससे पानी निकासी के पाइप मलबे से बंद हो गए हैं। बारिश का पानी खेतों में जमा हो रहा है। राकेश पाटीदार, जतिन पाटीदार और वीरेंद्र पाटीदार सहित अन्य किसानों ने शिकायत में बताया कि पानी की समस्या से परेशान होकर उन्होंने खुद पानी निकासी का रास्ता बनाया।

वीबी-जीरामजी योजना में ग्रामीणों को मिलेंगे 125 दिन रोजगार : विजय शाह

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● ग्रामीण मजदूरों को अधिक रोजगार और बेहतर आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जीरामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ गुरुवार को खंडवा ब्लॉक के ग्राम बमनगांव आखई में हुआ। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि यह योजना गरीब ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन तनवे, मांधाता विधायक नारायण पटेल, पंधाना विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, महापौर अमृता यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मंत्री विजय शाह ने कहा कि नई योजना में रोजगार मांगने के बावजूद काम नहीं मिलने पर पात्र मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी मजदूरी के साथ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार का अधिकार और अधिक प्रभावी एवं कानूनी रूप से मजबूत होगा।

भारतीय बैडमिंटन में लागू होगा नया स्कोरिंग सिस्टम

नई दिल्ली (एजेंसी) • भारतीय बैडमिंटन में जुलाई, 2026 से नया स्कोरिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत गेम 21 की जगह 15 अंक के होंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। नए नियमों का पहला इस्तेमाल सात से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम के रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा। इसके बाद यह फॉर्मेट सभी जोनल चैंपियनशिप, घरेलू रैंकिंग टूर्नामेंट और नेशनल चैंपियनशिप में लागू होगा। इसमें अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19, सीनियर और मास्टर्स सभी एज ग्रुप शामिल होंगे। नए फॉर्मेट में मैच पहले की तरह बेस्ट ऑफ-3 गेम ही होंगे, लेकिन अब हर गेम 21 की जगह 15 अंक का होगा। 14-14 की बराबरी होने पर दो अंकों की बढ़त जरूरी होगी। अगर स्कोर 20-20 तक पहुंचता है तो अगला अंक जीतने वाला खिलाड़ी गेम अपने नाम करेगा। अब मिड-गेम ब्रेक 11 अंक की बजाय आठ अंक पर मिलेगा और यह 60 सेकेंड का होगा। तीसरे गेम में खिलाड़ी आठ अंक पर कोर्ट बदलेंगे। गेम के बीच मिलने वाला 120 सेकंड का ब्रेक पहले की तरह जारी रहेगा और पिछले गेम का विजेता ही अगले गेम में पहली सर्विस करेगा। बीएआई महासचिव संजय मिश्रा ने कहा कि घरेलू स्तर पर नए फॉर्मेट को पहले लागू करने का उद्देश्य खिलाड़ियों, कोच और तकनीकी अधिकारियों को समय रहते इसकी आदत डालना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) इस स्कोरिंग सिस्टम को जनवरी, 2027 से इंटरनेशनल इवेंट में लागू करेगा।

टेबल टेनिस : अभिनंद-दिव्यांशी सेमीफाइनल में, पदक पक्का

नई दिल्ली (एजेंसी) • भारतीय टेबल टेनिस के उभरते सितारों ने बैंकॉक में चल रही एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारत की शीर्ष वरीय अंडर-19 मिश्रित युगल जोड़ी पी.बी. अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक ने खिताबी दावेदार चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को खेले गए हाई-प्रेशर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को धूल चटाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया और देश के लिए कम से कम कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक पक्का कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने पूरे मैच में ऐसा आक्रामक खेल और सटीक तालमेल दिखाया कि चीनी पैडलर्स यिरन तांग और यियी जियांग एक बार भी मुकाबले में वापसी नहीं कर सके। अभिनंद और दिव्यांशी ने यह मैच 11-9, 11-6, 11-7 से सीधे गेमों में एकतरफा अंदाज में अपने नाम किया। चीन के खिलाफ इस महा-मुकाबले से पहले भी भारतीय जोड़ी का जलवा देखने को मिला था। प्री-क्वार्टर फाइनल में अभिनंद और दिव्यांशी ने हांगकांग के एलीवन वोंग और सु त्सज तुंग की जोड़ी को 11-6, 11-8, 11-9 से हराकर अंतिम-8 में जगह बनाई थी।

सेंटनर की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उतरेगी न्यूजीलैंड

ऑकलैंड (एजेंसी) • न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी माह 12 जुलाई से होने वाली वाली पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए मिशेल सेंटनर को कप्तान बनाया है। 16 सदस्यीया टीम में पहली बार तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को शामिल किया गया है। फिशर ने अब तक केवल एक टेस्ट और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेला है। वह पहली बार किसी एकदिवसीय सीरीज के लिए शामिल किये गये हैं। ऐसे में उनका डेब्यू तय नजर आता है। कप्तान सेंटनर के अलावा, कई अनुभवी खिलाड़ी भी टीम में वापसी कर रहे हैं। इसमें डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल और जैकब डफी शामिल हैं। डफी हाल ही में पितृत्व अवकाश के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर थे।

वहीं कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है हैं। बांग्लादेश दौरे शामिल रहे अशोक, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, विल ओरूर्क और ब्लेयर टिकनर को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है जबकि तेज गेंदबाज मैट हेनरी और काइल जैमीसन को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है। ब्लेयर टिकनर टखने की सर्जरी के कारण इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण इंग्लैंड से सीधे स्वदेश लौटेंगे और इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र मेजर लीग क्रिकेट पहले से तय प्रतिबद्धताओं के चलते टीम के साथ नहीं जाएंगे। एकदिवसीय सीरीज के पहले तीन मुकाबले 12, 14 और 17 जुलाई को प्रोविडेंस, गुयाना में खेले जाएंगे। इसके बाद आखिरी दो मैच 20 और 22 जुलाई को केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की वनडे टीम इस प्रकार है: कप्तान मिशेल सेंटनर विकेटकीपर टॉम लैथम, मिशेल हे बल्लेबाज: मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, निक केली, विल यंग, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, क्रिस्टियन क्लार्क ऑलराउंडर: माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ गेंदबाज: मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, बेन सियर्स, जेडन लेनोक्स!

सोनी सब आ रही है 'चुड़ैल चली ससुराल'

मुंबई (एजेंसी) • सोनी सब ने अपने नए फैमिली सिटकॉम चुड़ैल चली ससुराल की घोषणा की है। फैंटेसी, कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामा पर आधारित इस शो में अभिनेत्री हिबा नवाब, राखी विजन और अधिक मेहता मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह शो जादुई दुनिया और आम पारिवारिक जीवन के दिलचस्प मेल के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करेगा। शो की कहानी उर्वशी (हिबा नवाब) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक दयालु चुड़ैल है और प्यार के लिए अपनी जादुई दुनिया छोडक़र आरव पटेल (अधिक मेहता) के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। इंसानी परिवार में सामंजस्य बैठाने की उसकी कोशिशें कई हास्यास्पद और अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा करती हैं। वहीं कामिनी (राखी विजन) एक शक्तिशाली चुड़ैल के रूप में उर्वशी के फैसले का विरोध करती है, जिससे जादू और पारिवारिक जीवन के बीच टकराव

की रोचक कहानी सामने आती है। हिबा नवाब ने कहा कि जैसे ही उन्होंने शो की कहानी सुनी, उन्हें विश्वास हो गया कि यह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग छह वर्ष बाद सोनी सब पर वापसी उनके लिए घर लौटने जैसी है और वह इस जादुई सफर को दर्शकों के साथ साझा करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' देखकर भावुक हुईं कृति

मुंबई (एजेंसी) • अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि इस फिल्म ने उन्हें अपने दिवंगत दादाजी और नानाजी की याद दिला दी तथा घर के मायने उनके लिए पूरी तरह बदल दिए। कृति ने अपने संदेश में लिखा कि फिल्म ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया और पिछली पीढ़ियों के त्याग तथा संघर्ष को नए नजरिये से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग अकसर उस जमीन को सामान्य मान लेते हैं, जिस पर वे खड़े हैं, जबकि वहां तक पहुंचने के लिए किसी ने अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी होती है। उन्होंने इम्तियाज़ अली की सराहना करते हुए लिखा कि आपकी फिल्में अकसर घर जैसी लगती हैं। इस बार घर नहीं मिला... इस बार घर की याद मिल गई। कृति ने कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि घर केवल वह जगह नहीं है जहां हम रहते हैं, बल्कि वह भावना भी है जहां शायद हम कभी लौट नहीं पाते। कृति ने फिल्म की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एक आम इंसान को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना संदेश अपने दादाजी, नानाजी और उन जैसे सभी आम लोगों को समर्पित करते हुए उनके योगदान को नमन किया।

उज्जैन संभाग

200 हेक्टेयर में बनेगा विश्वस्तरीय फॉरेस्ट जू, सिंहस्थ से पहले शुरू होगा पहला चरण

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • नवलखी के आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 200 हेक्टेयर में एक विश्वस्तरीय फॉरेस्ट जू विकसित किया जाएगा। वन विभाग के अनुसार, यह देश के सबसे आधुनिक और अनोखे प्राकृतिक फॉरेस्ट जू में से एक होगा, जो पर्यटकों को वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में करीब से देखने का अनुभव प्रदान करेगा। उज्जैन वन मंडल के डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि इस जू में 300 से अधिक वन्यजीव प्रजातियों को लाने का प्रस्ताव है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजे गए प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। यह परियोजना दो चरणों में विकसित की जाएगी। पहले चरण में लगभग 60 हेक्टेयर क्षेत्र में 'इंडिया ज़ोन' बनाया जाएगा। इसमें केवल भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रदर्शित किया जाएगा। इस ज़ोन में बड़े ड्राइव-थ्रू सफारी क्षेत्र, खुले प्राकृतिक बाड़े और आधुनिक आगंतुक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को जंगल जैसा वास्तविक अनुभव मिल सके। परियोजना के दूसरे चरण में 'फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड' थीम पर विकास कार्य होगा। इसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के वन्यजीवों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह जू अंतरराष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बन सकेगा। इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जू का क्षेत्र उज्जैन फोरलेन और पंचकोशी मार्ग से दो हिस्सों में विभाजित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने 35 मीटर चौड़ा ग्रीन ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस ओवरब्रिज पर पैदल चलने वालों और बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक सफारी के लिए अलग-अलग मार्ग होंगे। ब्रिज पर घने पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि वन्यजीवों पर शोर या दृश्य का प्रभाव न पड़े और आगंतुकों को भी जंगल जैसा अनुभव मिल सके।

रामघाट पर हादसा टला, शिप्रा में डूब रहे दो श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • रामघाट पर गुरुवार सुबह शिप्रा नदी में स्नान के दौरान डूब रहे उत्तर प्रदेश के दो श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) के जवानों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से आए विनय (35), प्रभात (28) और हर्ष (24) महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद सुबह रामघाट पर शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान प्रभात गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें बचाने के प्रयास में हर्ष भी गहरे पानी में फंस गए। जानकारी के मुताबिक हर्ष ने नदी में सुरक्षा के लिए लगाई गई फ्लोटिंग बॉल को पकड़ लिया, जिससे उन्हें कुछ देर तक सहारा मिल गया। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही रामघाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र डाबी और बनेसिंह तत्काल नदी में कूद पड़े।एसडीआरएफ के जवानों ने पहले प्रभात को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद हर्ष का भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। दोनों श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई। उल्लेखनीय है कि शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उज्जैन होमगार्ड द्वारा फ्लोटिंग बॉल के माध्यम से बैरिकेडिंग की गई है। इस घटना में यही सुरक्षा व्यवस्था बचाव कार्य में काफी मददगार साबित हुई और जवानों को दोनों श्रद्धालुओं तक शीघ्र पहुंचने में सहायता मिली।

ई-रिक्शा बैटरी लॉक कर रहे ठग, 300 रुपए मांगते हैं

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • ई-रिक्शा चालकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। मोबाइल ऐप के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच बनाकर वाहन बंद किए जा रहे थे। इसके बाद आरोपी खुद को मैकेनिक बताकर 200 से 300 रुपए लेकर ई-रिक्शा दोबारा चालू कर देता था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है। इसी तरह का मामला भोपाल में भी सामने आया है। शहर में करीब पांच हजार से अधिक ई-रिक्शा चलते हैं और बड़ी संख्या में महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु इनका उपयोग करते हैं। पिछले चार-पांच दिनों में आधा दर्जन से अधिक ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक बंद हो गए। हर बार एक युवक मौके पर पहुंचकर खुद को मैकेनिक बताता, 300 रुपए लेकर कुछ ही मिनटों में वाहन चालू कर देता था। लगातार एक जैसी घटनाओं के बाद ई-रिक्शा एसोसिएशन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने चालकों को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्ति की सूचना देने को कहा। बुधवार शाम लोटी स्कूल तिराहे पर एक ई-रिक्शा बंद हुआ। कुछ देर बाद एक युवक उसे ठीक करने के नाम पर 300 रुपए मांगने पहुंचा। चालक ने उसे पकड़कर पुलिस

के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान रीतेश भानूपा (18) निवासी ग्राम नवली, थाना भैरूगढ़ के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि वह मोबाइल एप के जरिए ब्लूटूथ से आसपास खड़े ई-रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच बना लेता था। इसके बाद वाहन बंद कर देता और फिर पैसे लेकर दोबारा चालू करता था।

ई-रिक्शा, ऑटो पर यूनिक आईडी लागू, 7 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • शहर में ई-रिक्शा और ऑटो व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से वाहनों पर यूनिक आईडी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नियम कल से लागू हो गया है, जिसके तहत अगले सात दिनों के भीतर यूनिक आईडी लगवाना अनिवार्य है। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और ऑटो चालक अपने वाहनों का पंजीकरण कराने तथा यूनिक आईडी बनवाने यातायात थाने पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा निर्धारित सात दिन की अवधि तक बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के यूनिक आईडी जारी की जा रही है। हालांकि, इस दौरान यातायात थानों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई-रिक्शा चालकों ने बताया कि उन्हें समाचार माध्यमों से जानकारी मिली है कि अब हर ई-रिक्शा पर यूनिक आईडी अनिवार्य है और इसके बिना वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण अधिकांश चालक कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते पंजीकरण कराने पहुंच रहे हैं। यूनिक आईडी बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से केंद्रों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। कई चालकों ने बताया कि उन्हें एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कल लगभग 30 से 40 वाहनों का पंजीकरण हुआ था और आज भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच, प्रशासन यातायात को कम करने के लिए एक नई संचालन व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इसके तहत, रात 3 बजे से दिन 3 बजे तक 2500 वाहन चलेंगे और फिर दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक अन्य 2500 वाहन संचालित होंगे। कुछ ई-रिक्शा चालकों ने इस नई संचालन व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। चालकों का कहना है कि यदि भविष्य में दिन और रात के हिसाब से संचालन तय किया जाता है, तो यह सभी के लिए व्यावहारिक नहीं होगा। कई चालकों ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कहा कि वे केवल दिन में ही वाहन चला सकते हैं।

कार पर स्टंट का वीडियो, वीआईपी रोड पर कार से बाहर लटक रहे थे युवक

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • चलती कार पर स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद माधव नगर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार जब्त कर ली और वाहन मालिक पर चालानी कार्रवाई की। बुधवार रात उज्जैन पुलिस की ट्रैफिक हेल्पलाइन पर एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें वीआईपी कोठी रोड पर कुछ युवक चलती मारुति नेक्सा सियाज से बाहर लटककर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे थे। पुलिस के अनुसार, उनका यह कृत्य न केवल उनके लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए माधव नगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया के नेतृत्व में वाहन और चालक की पहचान की गई। जांच में वाहन चालक की पहचान सूरज गोंदिया, पिता दौलतराम गोंदिया, निवासी भेरूनाला, थाना जीवाजीगंज, उज्जैन के रूप में हुई। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिया और चालक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

2028 तक पूरा फोकस सिंहस्थ पर, उसके बाद शुरू होगा स्टेशन री-डेवलपमेंट

चार साल तक और इंतजार : सिंहस्थ तक नहीं बदलेगा इंदौर स्टेशन, शास्त्री ब्रिज भी रहेगा

रेलवे महाप्रबंधक ने की तस्वीर साफ ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाई जाएगी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और शास्त्री ब्रिज को हटाने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर आखिरकार पश्चिम रेलवे ने तस्वीर साफ कर दी है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि रेलवे की पहली प्राथमिकता सिंहस्थ-2028 है। इसलिए इंदौर रेलवे स्टेशन का बड़े स्तर पर पुनर्विकास और शास्त्री ब्रिज हटाने का काम सिंहस्थ महापर्व के बाद ही शुरू होगा। इसका मतलब है कि शहरवासियों को आधुनिक रेलवे स्टेशन के लिए अभी लगभग चार वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। दो दिवसीय निरीक्षण दौरे पर इंदौर पहुंचे जीएम ने सांसद शंकर लालवानी के साथ पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सिंहस्थ से पहले स्टेशन पर कोई बड़ा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

फिलहाल निर्माणाधीन पार्सल बिल्डिंग का उपयोग अस्थायी यात्री सुविधाओं के लिए किया जाएगा, ताकि सिंहस्थ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के बाद शास्त्री ब्रिज हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की री-मॉडलिंग की जाएगी, जिसमें नए प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त रेल लाइनें और आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित होंगी। इससे ट्रेनों के संचालन की क्षमता भी बढ़ेगी। रेलवे का अनुमान है कि यह पूरा कार्य करीब दो वर्ष में पूरा होगा।

पार्किंग और यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी

सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए रेलवे परिसर में बड़े स्तर पर पार्किंग और यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 के बीच स्थित पुराने रिजर्वेशन कार्यालय और जीआरपी कार्यालय को हटाकर वहां विशाल पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही पत्थर गोदाम क्षेत्र की फिट लाइन को लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन स्थानांतरित करने की योजना है, जिससे भविष्य में दो अतिरिक्त रेलवे स्टेशन विकसित करने की संभावना भी बनेगी। जीएम रामाश्रय पांडेय ने कहा कि रतलाम मंडल में इंदौर रेलवे का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और आगामी वर्षों में स्टेशन विस्तार, नई रेल लाइनों तथा अधोसंरचना परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

इंदौर-दाहोद परियोजना की ली जानकारी

जीएम ने इंदौर-दाहोद रेल परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि टीही क्षेत्र में करीब तीन किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण अंतिम चरण में है। अब तक 1,660 मीटर से अधिक खुदाई पूरी हो चुकी है और 15 जुलाई तक लाइनिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू होगा। रेलवे को उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक परियोजना का मुख्य कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी।

अनुमति लंबित

वहीं इंदौर-खंडवा रेल परियोजना पर उन्होंने कहा कि वन एवं वन्यजीव संबंधी स्वीकृतियों में देरी के कारण काम प्रभावित हुआ है। पातालपानी के आगे फॉरेस्ट क्लीयरेंस और पेड़ों की कटाई की अनुमति लंबित है। राज्य सरकार से सहयोग मांगा गया है और वर्ष के अंत तक ओंकारेश्वर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

30-30 मीटर के छह स्पान पर गर्डर स्थापित, 180 मीटर है कुल लंबाई

अगस्त अंत में शुरू होगा बायपास एमआर 10 फ्लायओवर

अंडरपास से निकलेगा नेमावर तरफ फोरलेन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल बायपास-एमआर 10 चौराहे पर बन रहा फ्लायओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लायओवर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को अगस्त अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगस्त में फ्लायओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है।

24 माह में पूरा होना था, पौने तीन साल हो गए: अगस्त 2023 में शुरू हुई इस परियोजना को 24 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। अब परियोजना को शुरू हुए लगभग पौने तीन साल होने जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक डायवर्शन की जटिल व्यवस्था, भारी वाहनों की आवाजाही और फ्लाई ऐश से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों के कारण निर्माण की रफ्तार कई बार प्रभावित हुई। निर्माण के दौरान अक्टूबर 2025 में फ्लायओवर पर गर्डर लॉचिंग का काम शुरू हुआ था। 180 मीटर लंबे हिस्से में 30-30 मीटर के छह स्पान पर गर्डर स्थापित किए गए और दिसंबर 2025 तक यह कार्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद स्लैब निर्माण सहित अन्य संरचनात्मक कार्य किए गए। फिलहाल एप्रोच रोड, साइड कनेक्टिविटी, सुरक्षा बैरियर, और फिनिशिंग का काम चल रहा है।

बस स्टॉप बना जाम की वजह-सर्विस रोड पर बना अधोषित बस स्टॉप ट्रैफिक के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। पहले से ही सडक़ की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन धीमी गति से निकलते हैं। ऐसे में जब बसें यात्रियों को चढाने उतारने के लिए रुकती हैं तो पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। सुबह और शाम के पीक ऑवर में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है।

अंडरपास के लिए करना होगा इंतजार

फ्लायओवर शुरू होने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके नीचे प्रस्तावित हरदा रोड अंडरपास का निर्माण अभी बाकी है। अधिकारियों को अनुमान है कि इस हिस्से को पूरा होने में पांच से आठ महीने और लग सकते हैं। यानी फ्लायओवर से ट्रैफिक को राहत तो जल्द मिलेगी, लेकिन पूरे जंक्शन का विकास और निर्बाध यातायात व्यवस्था स्थापित होने में अभी कुछ और समय लगेगा।

हाईकोर्ट बार एसो. ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर जताई चिंता

इंदौर हाईकोर्ट में जजों की कमी से बढ़ते जा रहे लंबित मामले

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजा है।

एसोसिएशन का कहना है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गड़कर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में बताया गया है कि इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों के लगभग 13 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल सात न्यायमूर्ति ही कार्यरत हैं। हाल ही में प्रशासनिक न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों की संख्या और कम हो गई है। पत्र में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा गया है कि उन्होंने न्याय की गरिमा, न्यायिक अनुशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कार्य किया। एसोसिएशन ने कहा कि उनके सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्तता को शीघ्र भरना आवश्यक है, ताकि न्यायिक व्यवस्था प्रभावी और गतिशील बनी रहे। बार एसोसिएशन ने इस संबंध में भेजे गए पत्र की प्रति मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को भी प्रेषित की है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर इस विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे इंदौर खंडपीठ में न्यायिक कार्यों को गति मिलेगी और आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर दिया जोर

बार एसोसिएशन ने पत्र में उल्लेख किया है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण प्रकरणों के निराकरण की गति प्रभावित हो रही है। बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिससे अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि स्वीकृत पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

जनजातीय विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के मर्ज पर राज्यपाल को आपत्ति!

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्य प्रदेश में आदिवासी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने की प्रक्रिया पर नया मोड़ आ गया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासी स्कूलों को जनजातीय कार्य विभाग के तहत ही संचालित रखने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने की प्रक्रिया में पेंच फंस गया है। राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर ये कहा है कि स्कूलों के मामले में पहले जैसी व्यवस्था ही रखी जाए।

यानी आदिवासी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज न किया जाए। राज्यपाल ने सीएम को यह पत्र मध्य प्रदेश जनजातीय आयोग की आपत्ति के बाद लिखा है। आयोग ने राज्यपाल से निवेदन किया था कि यह व्यवस्था आदिवासी बच्चों के अनुकूल नहीं होगी इसलिए आदिवासी स्कूलों को जनजातीय विभाग के तहत ही संचालित किया जाए।

जनजातीय आयोग ने गवर्नर को लिखा पत्र : मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर रही है। सरकार की मंशा है कि सभी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत ही संचालित किया जाए।

अभी आदिवासी स्कूल जनजातीय विभाग के तहत आते हैं। आदिवासी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने पर मध्य प्रदेश जनजाति आयोग ने आपत्ति ली है। आयोग ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को पत्र लिखकर सारी स्थिति बताई है। आयोग के अध्यक्ष रामलाल रोतेल का कहना है कि आदिवासियों की संस्कृति अलग होती है इस मर्जर से सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। उनका कहना है कि आदिवासी स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक जाएं, वहां पर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो जिससे छात्र और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मर्जर इसका समाधान नहीं है। इस मौजूदा व्यवस्था के तहत ही आदिवासी छात्रों ने हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल में 90 फीसदी से ज्यादा सफलता हासिल की है। पत्र में लिखा है कि इस विषय पर परीक्षण कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए मौजूदा व्यवस्था को ही मजबूत किया जाए और उसे ही यथावत रखा जाए।

राज्यपाल का सीएम को पत्र

जानजातीय आयोग के पत्र पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को यथावत रखने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि मेरा मत है, कि जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अब तक प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों की निरन्तरता के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वर्तमान पृथक व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाये।
आशा है कि इस विषय पर संवेदनशीलता एवं दूरदृष्टि के साथ विचार कर जनजातीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा प्राथमिकता से की जा सकेगी। अब इस संबंध में सीएम मोहन यादव बैठक करने वाले हैं जिसमें इस पर फैसला लिया जाएगा।

यह है आदिवासी स्कूलों की स्थिति

- 20 जिलों में 88 विकासखंड में 26262 आदिवासी स्कूल
- शिक्षक 111763
- खाली शिक्षकों के पद 18456
- कुल छात्र 2145859
- 1100 हाईस्कूल में से 517 स्कूलों का रिजल्ट 100 फीसदी
- 804 हायर सेकंडरी स्कूल में से 156 स्कूलों का रिजल्ट 100 फीसदी

संचालन शुरू होने के एक माह बाद ही पहली बारिश ने ही दिखा दी गुणवत्ता

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग पहली ही तेज बारिश में टपकने लगी। 12 जून से इस भवन से स्टेशन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मानसून की पहली तेज बारिश में छत से कई जगह पानी का रिसाव होने लगा। इसके कारण भवन के अंदर कई स्थानों पर पानी जमा हो गया, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

बारिश के दौरान स्टेशन भवन के वेटिंग एरिया, कॉरिडोर और अन्य हिस्सों में छत से पानी टपकने की शिकायत सामने आई है। रिसाव के कारण फर्श पर पानी भर गया, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। नई बिल्डिंग शुरू होने के महज कुछ सप्ताह बाद ही सामने आई इस स्थिति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

यात्रियों का कहना है कि जिस भवन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, उसमें पहली ही बारिश में ऐसी खामियां सामने आना गंभीर मामला है। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। करीब 55 करोड़ रुपए की इस परियोजना में लगभग 45 करोड़ रुपए स्टेशन भवन और यात्री सुविधाओं पर तथा 10 करोड़ रुपए 36 फीट चौड़े फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। नए दो मंजिला स्टेशन भवन में तीन लिफ्ट, हाई लेवल प्लेटफॉर्म और आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं।

जब अभी ही ये हाल तो आगे क्या होगा-पहली ही तेज बारिश में नई बिल्डिंग में हुए रिसाव और परिसर में पानी जमा होने की स्थिति ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि शुरुआत में ही ऐसी स्थिति है तो भविष्य में यात्रियों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी की नजर रेलवे और निर्माण एजेंसी पर है कि इन खामियों को कब तक दूर किया जाता है।

लेटलतीफी के लिए चर्चित आईडीए में अब उठा सुरक्षा एजेंसी का घोटाला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा जारी सुरक्षा गार्ड टेंडर प्रक्रिया में झोल करने की पूरी तैयारी की जा रही हैं। वह इसलिए क्योंकि आईडीए ने 20 नवंबर 2024 को सुरक्षा एजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की थी। जिसमें बॉम्बे की सिक्योरिटी एजेंसी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी इंडिया का चयन किया गया था। लेकिन उक्त कंपनी के कई शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्टेड किए जाने की जानकारी मिलने पर उक्त निविदा प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा एजेंसी के चयन के लिए दोबारा 18 अप्रैल 2026 को निविदा आमंत्रित की। जिसमें निविदा शर्तों को ही बदल दिया गया। और सूत्र तो यहां तक बता रहे है कि इंदौर विकास प्राधिकरण के ही प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र पोरवाल सहित अन्य अमला पिछली प्रक्रिया में निविदा निरस्ती झेल चुकी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी इंडिया को आईडीए में दोबारा काबिज करने के लिए शर्तों को ही बदल चुके हैं। फिलहाल उक्त मामले की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संभागायुक्त सुदामा खाड़े सहित खुद इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े को भी शिकायत हो चुकी हैं। लेकिन उक्त शिकायत को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया हैं।

सिक्युरिटी एजेंसी के कामकाज की बात की जाए तो यह पूरा जिम्मा इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र पोरवाल की हैं। लिहाजा इंदौर विकास प्राधिकरण में पिछले 20 सालों से राजेंद्र पोरवाल के ही गुर्गे काबिज हैं। जिनमें सुपरवाइजर लवलेश मिश्रा प्रमुख हैं। आईडीए में इतने सालों में कितनी ही सुरक्षा गार्ड एजेंसिया आई हैं। लेकिन पोरवाल के खास गुर्गे लवलेश मिश्रा को कोई भी अधिकारी हटा नहीं पाया न ही कोई सुरक्षा एजेंसी। क्योंकि बताया जाता है कि पोरवाल की एक ही शर्त होती है सुरक्षा गार्ड एजेंसी कोई भी हो लेकिन सुपरवाइजर बनेगा तो सिर्फ लवलेश मिश्रा हैं। दरअसल इन्हीं वजह से आईडीए प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र पोरवाल ने कई टेंडर प्रक्रिया को तक निरस्त करवा दिया। लेकिन अपने गुर्गे को यहां से हटने नहीं दिया। इंदौर विकास प्राधिकरण के ही विश्वनीय सूत्र बताते है कि सुरक्षा गार्डों की प्रतिमाह दी जाने वाली सेलरी को लेकर भी बड़ा खेला होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।